शुक्रवार
12 जुलाई 2024

पृष्ठ 4
नींद लेने के नाम से दिल में दस्तक देता..

पृष्ठ 5
अभिनेत्री मालविका की तस्वीरों ने...

● देहरादून
● वर्ष 32
● अंक 158
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

आज का विचार

प्रकृति, समय और धैर्य ये तीन हर दर्द की दवा हैं।
– अज्ञात

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक
आर.एन.आई.- 59626/94
email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com
डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

यूसीसी का ड्राफ्ट हुआ सार्वजनिक

विशेष संवाददाता

देहरादून। समान नागरिक संहिता की संपूर्ण रिपोर्ट को आज आम आदमी के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। विभिन्न मुद्दों को लेकर जो नई आचार संहिता उत्तराखंड और इसके साथ ही अन्य राज्यों में लागू करने की जो बात कहीं जा रही है उसके अंदर क्या-क्या व्यवस्था होगी इसके बारे में अब आप सब कुछ जान सकते हैं।

चार खण्डों में हिंदी और अंग्रेजी में यह यूसीसी का ड्राफ्ट अब समिति द्वारा सरकार के आदेश पर वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब कोई भी इसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट यूसीसी डॉट जीओवी पर जाकर देख सकता हैं।

❑अक्टूबर माह तक राज्य में लागू हो जाएगा यूसीसी

आज एक पत्रकार वार्ता में इस आशय की जानकारी समिति सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा दी गई। इस अवसर पर समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सिन्हा ने बताया कि यूसीसी भारत से पहले अन्य तमाम देशों में लागू हो चुका है।

उन्होंने इस अवसर पर फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश सहित तमाम राष्ट्रों में इस व्यवस्था के स्वरूप की जानकारी देते हुए बताया कि यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी द्वारा तमाम देशों की यूसीसी व्यवस्था और किस मुद्दे पर कब-कब किस-किस देश ने क्या-क्या संशोधन किये उनका अध्ययन कर उसका सहारा भी इस ड्रॉप्ट को तैयार करने में लिया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान यूसीसी लागू करने का जो संकल्प लिया गया उसे अब पूर्णता की ओर ले जाने का समय आ गया है। 27 मई 2022 को सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति ड्रॉप्ट तैयार करने के लिए बनाई गई थी। जिसने तमाम स्थितियों व परिस्थितियों के अध्ययन के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों को बिना प्रभावित किये एक ऐसा यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया जिससे देश के सभी जाति-धर्म और समुदाय के लिए एक ही तरह के कानून की व्यवस्था बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि अब यह पब्लिक डोमेन में आ गया है और सरकार इसे जल्द अमलीजामा पहनाने जा रही है। अक्टूबर माह तक राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा।

गेस्ट हाउस में चल रहा था देह व्यापार, 8 महिलाओं सहित 19 लोग गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भडांफोड़ करते हुए पुलिस व एएचटीयू टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर 8 महिलाओं सहित 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से देहव्यापार के लिए लाई गयी नाबालिक को भी रेस्क्यू किया गया है।

जानकारी के अनुसार बीते रोज कलियर थाना पुलिस व एएचटीयू टीम को सूचना मिली कि कलियर क्षेत्रांतर्गत रहमत साबरी गेस्ट हाउस सोहलपुर रोड पर कुछ लोग सैक्स रैकेट चला रहे है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस व एएचटीयू टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए बताये गये गेस्ट हाउस में छापेमारी की गयी। अचानक पुलिस की छापेमारी करने पर वहां मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान संयुक्त टीम ने वहां से 8 महिलाओं व

11 पुरुषों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सयुंक्त टीम ने इस दौरान आरोपियों के कब्जे से एक नाबालिग को भी रेस्क्यू किया गया जिसे आरोपी देह व्यापार के लिए लाये थे।

पुलिस के अनुसार इस सैक्स रैकेट का मुख्य आरोपी मुस्तफा पुत्र रसीद काफी समय से गिरोह बनाकर देह व्यापार का धंधा चला रहा था। वह अपने गेस्ट हाउस पर बाहर से गरीब महिलाओं व लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर ग्राहकों का इंतजाम कर देह व्यापार करवाता था जिसके पूर्व में भी कई मामले दर्ज है। ▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। आप संयोजक को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में शीर्ष न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को 90 दिनों की जेल हुई है और उसे पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। यह सुनवाई ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर की गई। कोर्ट के फैसले के बावजूद केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें 25 जून को शराब नीति से जुड़े इसी मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

वही दूसरी ओर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। राउज ऐवन्यू कोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। सीएम केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि वे उनके खिलाफ ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

नेपाल में लैंडस्लाइड के कारण यात्रियों से भरी दो बसें त्रिशूली नदी में गिरी

नई दिल्ली। नेपाल में लैंडस्लाइड के कारण यात्रियों से भरी दो बसें त्रिशूली नदी में बह गईं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों बसों में करीब 63 यात्री सवार थे। हादसे के बाद राहत व बचाव अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश के कारण लापता बसों को खोजना मुश्किल हो रहा है।

नेपाल के चितवन जिले के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि यह हादसा आज सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। भूस्खलन के कारण लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही दो बसें त्रिशूली नदी में बह गईं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों बसों में बस चालकों

सहित कुल 63 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि हम घटनास्थल पर हैं और तलाशी अभियान चल रहा है। लगातार बारिश के कारण लापता बसों की तलाश में हमें दिक्कत आ रही है।

पुलिस के अनुसार, काठमांडू जा रही एंजेल बस में 24 और गणपति डीलक्स बस में 41 लोग सवार थे। हालांकि, गणपति डीलक्स में सवार तीन यात्री बस के नदी में बहने से पहले कूदने में सफल रहे। यह हादसा सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, नारायणगढ़-मुग्लिन सड़क खंड पर भूस्खलन में बस के बह जाने से लगभग पांच दर्जन यात्रियों के लापता होने की रिपोर्ट और देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण संपत्तियों के नुकसान से मैं बहुत दुखी हूं। मैं गृह प्रशासन सहित सरकार की सभी एजेंसियों को यात्रियों की खोज और प्रभावी बचाव के निर्देश देता हूं।

दून वैली मेल

संपादकीय

अग्निवीर पर फंसी सरकार

बीते 10 सालों में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 'न खाता न बही जो सरकार कहे वही सही, की नीतियों पर चलते हुए जिस तरह काम किया गया वह अब आगे किसी भी कीमत पर चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब सरकार के सामने एक ऐसा मजबूत विपक्ष बैठा है जो उसे मनमानी नहीं करने देगा। यह बात संसद के पहले ही सत्र में साफ हो चुकी है। राहुल गांधी के भाषणों के दौरान सफाईयां पेश करने के लिए दंड बैठक करने वाले मंत्रियों और अखिलेश द्वारा सदन में साफ-साफ यह कहे जाने कि अब सरकार मनमर्जी से नहीं जनमर्जी से चलेगी यह साफ हो गया है कि सरकार की तानाशाही के दिन अब लद चुके हैं। विपक्ष द्वारा इस चुनाव में जिन मुद्दों को उठाया गया था अब उन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया गया है। बात चाहे उस योजना की हो जिसे अग्निपथ के नाम से सरकार ने लांच किया था या पेपर लीक और बेरोजगारी की। खास बात यह है कि विपक्षी नेताओं की गलतियां गिनाने व उन्हें बालक बुद्धि की गलतियां न समझ कर ईंट का जवाब ईंट से देने की बात करने वाली सरकार ने अब अपने गलत फैसलों पर लीपा पोती का काम शुरू कर दिया है क्योंकि उनके पास अपने गलतियों को सही ठहराने का कोई जरिया ही नहीं बचा है। जिस अग्निवीर के मुद्दे पर संसद में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री) के बीच तीखी झड़पे हुई थी उस अग्नि वीर योजना पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी पांच प्रमुखों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी देने के नियमों में बदलाव करने की घोषणा की गई है। सभी अर्धसैनिक बलों में अब अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा तथा उन्हें आयु सीमा में छूट भी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संसदीय समिति की बैठक में इस बात की भी सिफारिश की गई है कि रेगुलर सैनिकों की तरह अग्निवीरों को शहीद होने की स्थिति में वही सब सहुलियते मिलनी चाहिए जो रेगुलर सैनिकों को मिलती है। इस बात का सीधा अर्थ यही है कि विपक्ष के दबाव के कारण आखिर सरकार को यह मानने पर मजबूर होना ही पड़ा है कि सेना में दो तरह के शहीद नहीं हो सकते या नहीं होने चाहिए। जबकि अग्निवीर के शहीदी के स्थिति में पहले तो इन्हें शहीद ही नहीं माना जा रहा था एक रेगुलर सैनिक को उसके अंतिम वेतन के बराबर पेंशन आजीवन दी जाती है लेकिन अग्नि वीर को किसी भी तरह की पेंशन नहीं दी जाती है शहीद सैनिक को जिस तरह वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है वैसे अग्नि वीरों के लिए किसी चक्र को देने का प्रावधान नहीं था एक रेगुलर सैनिक को लगभग 30 प्रकार की तमाम सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और यात्राओं से लेकर कैंटीन आदि की सुविधा दी जाती है लेकिन अग्नि वीरों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। क्या किसी भी देश में सैनिकों के लिए दो तरह के मापदंड उचित हो सकते हैं तथा इसका सैनिकों के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। भले ही पहले सत्ता में बैठे लोगों को यह बात समझ में न आई हो लेकिन अब उन्हें यह अच्छे से समझ आ गया है कि यह फैसला गलत था। विपक्ष जो सत्ता में आने पर अग्नि वीर योजना को रद्द करने की बात कह रहा है, की तरह सरकार अब इसे रद्द करने का साहस तो दिखा नहीं सकती है इसलिए अब योजना के नियम बदलकर अपनी गलती पर लीपा पोती तो कर ही सकती है।

क्लीन एण्ड ग्रीन एन्वायरमेंट संस्था ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा

❑दशहरा मैदान में हो रहे निर्माण कार्य की जांच खेल विभाग को सौंपी

संवाददाता

देहरादून। क्लीन एण्ड ग्रीन इन्वायरमेंट संस्था ने मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान को दशहरा मैदान में हो रहे निर्माण कार्य के कारण एक बच्चे की मौत के बारे में लिखित जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जांच निदेशक युवा एवं खेल विभाग को सौंप दी।

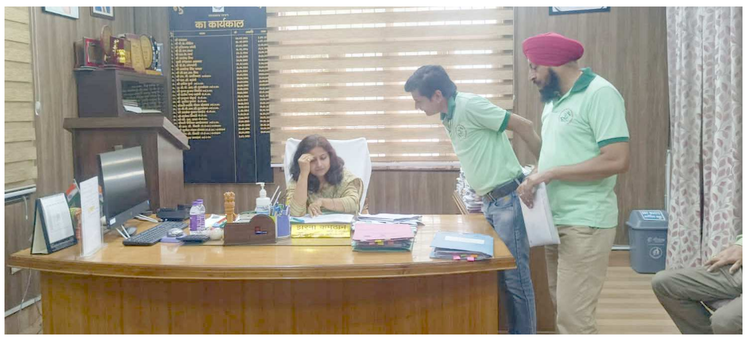

आज यहां क्लीन एण्ड ग्रीन एन्वायरमेंट संस्था के अध्यक्ष व संस्थापक राम कपूर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रेमनगर के दशहरा मैदान में विधायक निधि से बनाये जा रहे मिनी स्टेडियम के निर्माण में ग्राउण्ड में खोदे गये गढडे में डूबने से पांच वर्ष के बच्चे की मौत हो गयी। उन्होंने कहा कि दशहरा ग्राउण्ड में जिस निर्माण कार्य के कारण मासूम बच्चे की जान गयी है वह निर्माण कार्य व्यर्थ एवं अनुपयोगी निर्माण कार्य हैं। निर्माण कार्य के कारण दशहरा मैदान जो कि देहरादून का सर्वप्रथम दशहरा मैदान है अपनी पहचान खो देगा। उन्होंने कहा कि देश विभाजन के बाद 1948 से लगातार दशहरा पर्व इसी दशहरा ग्राउण्ड में अभी तक मनाया जाता है। इसी वजह से इस मैदान का नाम दशहरा मैदान पडा है। देहरादून में सर्वप्रथम लंका दहन और रावत जलाना यहीं से शुरू हुआ था जो कि इस निर्माण कार्य के चलते वर्ष 2024 या उससे आगे के समय दशहरा कार्यक्रम इस मैदान पर होना सम्भव नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि दशहरा मैदान में हो रहे निर्माण कार्य के दौरान हुई लापरवाही जिसमें एक निर्धन परिवार के बच्चे की जान गयी है के दोषियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही तथा निर्माण कार्य में संलग्न कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का पंजीकरण रदद एवं उन्हें ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जाये। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने अधिकारियों को तलब किया तो पता चला कि वह विधायक निधि से हो रहा निर्माण कार्य बताया जा रहा है वह मुख्यमंत्री की घोषणा निकली।

मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जांच निदेशक युवा एवं खेल विभाग को सौंप दी।

शराब के साथ दो गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चैकिंग के दौरान जंगलात बैरियर के पास एक स्कूटी सवार दो लोगों को रूकने का इशारा किया तो वह पुलिस को देख भाग खडे हुए।

पुलिस ने पीछा कर उनको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके थैले से 120 पव्वे शराब के बरामद हो गये। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम मनोज जाटव पुत्र भगवत प्रसाद, बिटटू जाटव पुत्र रतिराम दोनों निवासी जाटव बस्ती बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी माहरा को जन्मदिन की बधाई

संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा को जन्म दिन की बधाई दी। आज यहां कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पूर्व विधान सभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुंजवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, मथुरा दत्त जोशी, गोदावरी थापली, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी समेत पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

पीसीएस परीक्षा 14 को

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2024 (पीसीएस) का आयोजन प्रदेश के कुल 405 केन्द्रों पर 14 जुलाई को दो सत्रों में किया जायेगा।

आज यहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2024 (पीसीएस) का आयोजन प्रदेश के कुल 405 केन्द्रों पर 14 जुलाई, 2024 को दो सत्रों में किया जाएगा। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा हेतु समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गयी हैं।

उन्होंने बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष एवं शुचितापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु आयोग और शासन द्वारा सुरक्षा तथा गोपनीयता से संबन्धित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी हैं। सभी परीक्षा केन्द्रों और उनके निकटवर्ती स्थानों पर पुलिस/प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं और अफवाहों से दूर रहें।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग या परीक्षा की गोपनीयता भंग करने के प्रयास करने वालों के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा नकल विरोधी अधिनियम-2023 व अन्य संगत कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी और ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वर्षा ऋतु के दृष्टिगत अपने परीक्षा केन्द्र वाले गन्तव्य शहर में पर्याप्त समय पूर्व पहुँच जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

ई-रिक्शा संचालकों को उनका हक दिलाकर रहेगा मोर्चा: नेगी

संवाददाता

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा ई-रिक्शा संचालकों को उनका हक दिलाकर रहेगा।

आज यहां ई- रिक्शा संचालकों की पीड़ा को देखते हुए उनके बीच में उनका हक दिलाने मोर्चा के साथियों संग पहुंचे जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने उनकी पीड़ा सुनी, जिसमें संचालकों ने अपने-अपने विचार व्यक्त कर भिन्न-भिन्न रूटों पर चलने वाले ई-रिक्शा से संबंधित सुझाव रखे, जिसमें मुख्य रूप से रूट चार्ट बनाने,एक ही जगह ई-रिक्शा न खड़े करने तथा यातायात में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने पर बल दिया गया। नेगी ने ई- रिक्शा संचालकों की बैठक में संचालकों को आश्वासन दिया कि किसी भी सूरत में मोर्चा इनका उत्पीड़न नहीं होने देगा , लेकिन संचालकों को भी

यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करना होगा ताकि अनावश्यक रूप से शहर में जाम की स्थिति न बने एवं एक ही जगह झुंड के रूप में इकट्ठे न हो। सभी का दायित्व बनता है कि यातायात सुचारू रखने में पुलिस- प्रशासन का सहयोग एवं जनता की परेशानियां का भी ध्यान रखें। बैठक में सभी रूटों के अध्यक्षों का चयन एवं दो-तीन दिन के भीतर सुझाव मोर्चा के समक्ष रखने का प्रस्ताव आया। नेगी ने कहा कि इस संबंध में बैठक में हुए तथ्यों से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी, विकास नगर को अवगत कराया जाएगा, जिससे भविष्य में इनका शोषण न हो सके।बैठक में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विजय राम शर्मा, मोहम्मद असद, प्रवीण शर्मा पिन्नी, नदीम तथा ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष अश्वनी प्रसाद, बिल्लू गिल्बर्ट, जगबीर, सफीक पांडे, भगत, नाजिर, सोनू, सलमान, चरण सिंह, संदीप,बाबू ,अरविंद रोहिल्ला, अनिल आदि शामिल थे।

मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में करायी जायेः माहरा

संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उपचुनावों की मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में करायी जाये।

आज यहां उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने मंगलौर एवं बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनावों की मतगणना सीसी टीवी कैमरों की निगरानी में कराए जाने तथा मतगणना स्थल पर निर्वाचन अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों की मौजूदगी प्रतिबन्धित कराये जाने की मांग की है। माहरा ने कहा कि 13 जुलाई, 2024 को उत्तराखण्ड प्रदेश के 4-बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र एवं 33-मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना सम्पन्न होनी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में भी कई बार शिकायत दर्ज की गई थी कि भाजपा सरकार द्वारा चुनाव प्रचार एवं मतदान के दौरान सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। यही नहीं मतदान के दौरान 10 जुलाई को मंगलौर विधानसभा के लिब्बरहेड़ी में पुलिस प्रशासन एवं मतदान कर्मियों की मौजूदगी में गोलीबारी एवं मारपीट की घटना सामने आई। जिसके तहत बाहरी राज्यों से आये गुंडा तत्वों द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिब्बरहेड़ी के बूथ नम्बर 53-54 में मतदाताओं पर लाठी डंडों से प्रहार किया गया तथा गैर कानूनी हथियारों से कई राउंड हवाई फायरिंग की गई जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। करन माहरा ने कहा कि जिस प्रकार चुनाव प्रचार एवं मतदान के दौरान घटनाएं घटित हुई हैं इससे कांग्रेस पार्टी को मतगणना के दिन भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने के साथ ही भारी गडबडी की आशंका है। उन्होंने कहा कि मतगणना की निष्पक्षता के लिए आवश्यक है कि बद्रीनाथ एवं मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर निर्वाचन अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाय। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना हेतु विशेष आब्जर्बर नियुक्त किया जाय तथा दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना सी.सी. टीवी कैमरे की निगरानी में कराई जाय।

समिति ने विश्व जनसंख्या दिवस पर रखी विचार गोष्ठी

संवाददाता

देहरादून। नेताजी संघर्ष समिति ने विश्व जनसंख्या दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। यहां नेताजी संघर्ष समिति के कार्यालय कावली रोड पर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया गोष्ठी की अध्यक्षता प्रभात डंडरियाल और संचालन आरिफ वारसी ने किया गोष्ठी में वक्ताओं ने देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर गहरी चिंता जताई। प्रभात डंडरियाल और आरिफ वारसी ने कहा की जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जन जागरण अभियान भी चलने चाहिए ये भी समय की मांग है। जनजागरण कर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए अगर जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो एक दिन सभी के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो जायेगी। इस गोष्ठी में प्रभात डंडरियाल, आरिफ वारसी, अतुल शर्मा, पारस यादव, रणजीत सिंह जोशी, प्रदीप कुकरेती, इम्तियाज अहमद, संदीप गुप्ता, राम सिंह कश्यप, दानिश नूर आदि उपस्थित रहे।

तड़ीपार बदमाश आया पुलिस की गिरफ्त में, भेजा जेल

हमारे संवाददाता

पौड़ी। जिला बदर (तड़ीपार) किये गये बदमाश को वापस आकर घर में छुपकर रहना भारी पड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार जिले में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका और सुधरने का नाम नही ले रहे बदमाश वसीम के खिलाफ कोटद्वार पुलिस द्वारा उ. प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3 (क) की कार्यवाही कर आरोपी को छः माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) की कार्यवाही कर जनपद पौड़ी की सीमा से बाहर भेजा गया था।

बीते रोज थाना कोटद्वार पुलिस को सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी वसीम तड़ीपार होने के बाद भी छः माह से पूर्व अपने घर में वापस आकर छिपकर रह रहा है। जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी वसीम को घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी वसीम पुत्र मुख्त्यार निवासी कौडिया, कोतवाली कोटद्वार, जनपद पौडी गढवाल के खिलाफ पूर्व में दिनांक-18.02.2024 को जिला बदर की कार्यवाही की गयी थी । आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह कुछ समय उत्तर प्रदेश व अलग-अलग जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहां निवास करने के बाद चुपके से अपने घर में निवास कर रहा था। क्योकि आरोपी द्वारा उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 03/10 का उल्लंघन किया गया है अतः पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कोटद्वार में मु.अ.सं.-181/24, धारा-3/10 उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) गुण्डा अधिनियम 1970 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

घर के लिए पौधे खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान!

अगर आप अपने घर को तरह-तरह के पौधों से सजाने पर विचार कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के लिए कौन सा पौधा बेहतरीन है। दरअसल, हर घर के साथ-साथ पौधों की जरूरतें भी अलग होती हैं, इसलिए सही पौधे का चयन करना बेहद आवश्यक है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने घर के लिए बेहतरीन पौधे खरीद सकते हैं।

पौधे साइज पर दें ध्यान

अगर आप अपने घर के लिए पौधे खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उनके साइज पर खास ध्यान दें। बता दें कि आजकल मार्केट में मौजूद छोटे और बड़े पौधों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। उदाहरण के लिए एक-दो फीट के पौधे की कीमत 5-6 फीट लंबे पौधे से कम हो सकती है। इसलिए जब भी आप पौधे खरीदें तो उसका साइज अपने बजट और अपने घर की जगह के अनुसार ही चुनें।

पौधे को अच्छे से करें चेक

किसी भी तरह के पौधे को घर लाने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करना बहुत जरूरी है। बेहतर होगा कि आप ऐसे किसी भी पौधे को न लाएं, जो कमजोर नजर आए या फिर क्षतिग्रस्त हो। बता दें कि अच्छे पौधे की पत्तियां नरम और ताजी नजर आती हैं। वहीं, अगर आप पत्तियों पर धब्बे और निशान या फिर पीली दिखें तो यह किसी बीमारी या संक्रमण के कारण हो सकता है।

लेबल को जरूर पढ़ें

घर के लिए पौधे खरीदते समय उसके लेबल को ठीक से पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि लेबल को अच्छी तरह से पढ़ने से आपको पौधे के लिए प्रकाश, पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसके साथ ही कुछ लेबल इनके रखरखाव के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। हालांकि, अगर प्लांट पर लेबल नहीं है तो ऐसे में आप उस प्लांट की जानकारी को पहले इंटरनेट पर चेक करें।

कीड़े आदि हो तो न खरीदें पौधे

जब भी आप घर के लिए पौधे खरीदें तो यह जरूर चेक कर लें कि उसमें कोई कीड़ा न हो। आमतौर पर कीड़े या कीट पत्ते के नीचे या पौधों के तने पर छिप जाते हैं, जिससे उन्हें एक बार में पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी भी पौधे को खरीदने से पहले उसमें कीड़ों का पता जरूर लगाएं। इसके अलावा, ठीक से जांच लें कि क्या पौधे में काले धब्बे, छेद, छाले या पत्ते चिपचिपे तो नहीं हैं।

छोटी अलमारी को व्यवस्थित करते समय न करें ये गलतियां

अगर अलमारी बड़ी होती है तो उसे व्यवस्थित करने में परेशानी नहीं आती, लेकिन जब बात छोटी अलमारी की आती है तो उसे व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दरअसल, कम जगह में अधिक सामान को व्यवस्थित करके रखना आसान काम नहीं होता। इसलिए कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिससे काम और मेहनत दोनों ही बढ़ जाती हैं। आइए आज ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।

यह छोटी अलमारी को व्यवस्थित करते समय की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। दरअसल, जब भी बात अलमारी को व्यवस्थित करने की आती है तो कई लोग इसे खाली करना या फिर इसमें मौजूद सामान की छांटा-छांटी करना जरूरी नहीं समझते, जिसके कारण सिर्फ समय ही बर्बाद होता है। इसलिए जब भी आप अपनी अलमारी को व्यवस्थित करें तो पहले उसे खाली करें और जो सामान इस्तेमाल करने लायक नहीं है, उसे बाहर कर दें।

अगर आपको लगता है कि इस गलती से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो आप गलत हैं क्योंकि इसके कारण आप अपनी छोटी अलमारी को ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। आजकल मार्केट में विभिन्न आकार और डिजाअन्स के हैंगर मिलते हैं। ऐसे में जब भी आप अपनी अलमारी को आर्गेनाइज करें तो यह अवश्य देखें कि हैंगर्स आपकी अलमारी के साइज के अनुसार सही हो। इसके साथ ही सभी हैंगर्स एक ही आकार और डिजाइन के होने चाहिए। हम लोग घर को व्यवस्थित करने के लिए किसी भी तरह के डिवाइडर से लेकर स्टोरेज बॉक्स आदि कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटी अलमारी को व्यवस्थित करते समय गलत आर्गेनाइजर का चयन करना बड़ी गलती है। ऐसा करने से आपकी अलमारी की जगह अधिक घिरेगी, जिससे सामान को बेहतर तरीके से रखना मुश्किल होगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी अलमारी के लिए फ्लैट शेल्फ डिवाइडर या फिर हैंगिंग आर्गेनाइजर का इस्तेमाल करें।

एड़ियों में बार-बार दर्द होता है? जानिए इसके कारण

एड़ियों में दर्द होना एक कष्टदायक समस्या है जिसे नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको बार-बार एड़ियों में दर्द का सामना करना पड़ता है तो आपके लिए इसके पीछे का कारण जानना जरूरी है ताकि उसके मुताबिक समस्या का सही उपचार किया जा सके। आइए आज आपको ऐसे ही कुछ मुख्य कारणों के बारे में बताते हैं जो एड़ियों में दर्द उत्पन्न कर सकते हैं।

गलत साइज के जूते और चप्पल पहनना

यह एड़ियों में दर्द होने का मुख्य कारण हो सकता है। दरअसल, अगर आप गलत साइज के जूते या फिर खराब सोल वाली चप्पल पहनते हैं तो इसके कारण एड़ियों में दर्द होने लगता है। इसलिए जब भी आप अपने लिए जूते या फिर चप्पल खरीदें तो साइज और इनकी सोल पर विशेष ध्यान दें, ताकि इन्हें पहनकर चलने में न तो एड़ियों में दर्द हो और न ही किसी तरह की अन्य परेशानी हो।

शारीरिक सक्रियता में कमी

अगर आप घर में घंटों तक एक जगह बैठकर अपना पूरा दिन निकाल देते हैं यानि शारीरिक कामकाज कम करते

हैं तो इस वजह से आपको एड़ियों में दर्द हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम के दौरान एक जगह बैठकर काफी देर तक लैपटॉप पर ऑफिस का काम करते है और एक्सरसाइज या चलने-फिरने का काम नहीं करते हैं तो इसके कारण आपको एड़ियों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

हैग्लंड की विकृति बीमारी

हैग्लंड की विकृति एड़ी की हड्डियों से जुड़ी एक बीमारी है जो एड़ियों में दर्द का कारण बन सकती है। ये बीमारी तब होती है जब आपकी एड़ी के पिछले हिस्से पर बार-बार दबाव पड़ता है। यह बहुत तंग फुटवियर्स पहनने के कारण हो सकती है। आजकल कई महिलाएं हिल्स पहनना काफी पसंद करती हैं, लेकिन इससे एड़ियों पर काफी दबाव पड़ता है जिसके कारण हैग्लंड की विकृति हो सकती है।

फुट बर्साइटिस की समस्या

फुट बर्साइटिस एड़ियों से जुड़ी एक समस्या है। यह समस्या तब होती है जब हमारी एड़ियों में मौजूद बर्सा चोटिल हो जाती है या इसमें सूजन आ जाती है। बर्सा एक छोटी द्रव से भरी थैली होती है जो एड़ियों के जोड़ और हड्डियों को चिकनाई देती है। इसके कारण आपको बार-बार एड़ियों में तेज दर्द, सूजन और लालिमा जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

राहुल गांधी का राजनीतिक उत्थान

प्रभु चावला

एक तस्वीर हजार शब्दों के समान होती है। पिछले दिनों एक तस्वीर आयी, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हाथ मिला रहे हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उनके पीछे खड़े हैं। मोदी और राहुल परंपरा के अनुसार बिरला को आसन तक ले गये थे। विपक्ष की पहली कतार में आने में राहुल को दो दशक का समय लगा है। उनके माता-पिता भी प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। कभी ऐसा दौर भी था, जब वे संसद को खास अहमियत नहीं देते थे। मोदी को घेरने में कांग्रेस नाकाम रही क्योंकि राहुल द्वारा नामित नेता प्रभावी नहीं थे। इस बार मोदी का सामना करने के लिए उन्हें आगे रहना होगा। उनके आचरण और प्रदर्शन से राजनीति में उनका कद निर्धारित होगा। कांग्रेस अपने बूते सरकार नहीं बना सकती है। राहुल गांधी को अगले गांधी युग के लिए साजो-सामान का आविष्कार करना होगा। उन्हें अर्जुन के कौशल और शकुनि की चतुराई की आवश्यकता है ताकि वे वैचारिक रूप से भिन्न और महत्वाकांक्षी सहयोगियों को साध सकें।

उनके पक्ष में आयु और सामाजिक स्वीकार्यता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से तथा आयु के हिसाब से उनके गठबंधन के सभी नेता अनुकूल हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, कनिमोजी, उमर अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और आदित्य ठाकरे राहुल के स्वाभाविक सहयोगी हैं। द्रमुक एवं राजद ने उन्हें प्रधानमंत्री के लिए अपनी पसंद बता दिया है। पर सभी को अपने प्रभाव क्षेत्र को बचाना और बढ़ाना है। राहुल के लिए यह अच्छी बात है कि कई राज्यों में कांग्रेस के पास खोने को कुछ खास नहीं है। वे अन्यों के वर्चस्व को स्वीकार कर सकते हैं और कुछ समय के लिए रणनीतिक रूप से पीछे हट सकते हैं। सोनिया गांधी अपने पूर्व आलोचक शरद पवार के साथ नाराजगी दूर कर तथा यूपीए सहयोगियों को अहम, मंत्रालय देकर 2004 में कांग्रेस को सत्ता में लायी थीं। यह एक सबक है। लोकसभा में मोदी के धार को कुंद करना राहुल की बड़ी चुनौती होगी।

राहुल धारदार वक्ता नहीं हैं। उन्हें मोदी की राजनीति, आर्थिक नीति और कूटनीति में कमियां निकालने की कला सीखनी होगी। मोदी ने एक चुनौतीविहीन शासक की तरह राज्य और केंद्र में सरकार चलाया है। अब उन्हें अपने सहयोगियों की मांगों का भी ध्यान रखना होगा। या तो वे उन्हें मानेंगे या गलतियां करेंगे। राहुल सही मौके का फायदा उठा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें हर क्षण मोदी का सामना करना होगा। उन्हें विशेषज्ञ शोधार्थियों और सलाहकारों की आवश्यकता होगी, जो उन्हें अर्थशास्त्र, राजनीति, सरकार प्रबंधन, रक्षा, विदेश संबंध और पर्यावरण पर राय दे सकें। उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी, जो प्रभावी ढंग से नैरेटिव का जवाब दे सकें। क्या राहुल की विचारधारा नेहरू से मेल खाती है? उनके भाषणों से लगता है कि उन्होंने फेबियन समाजवाद के विचार को अपनाया है। 'दो भारत' की उनकी बात नेहरू से ली गयी है। सम्मोहक नारे, बड़े आंकड़े और अजीब लक्ष्य मोदी की ताकत के हिस्से हैं। चूंकि दोनों हमेशा टकराव की स्थिति में होंगे, इसलिए राहुल को नये कौशल सीखने होंगे। हर गांधी ने अपना नया कांग्रेस बनाया था। नेहरू को ऐसी पार्टी मिली थी, जो उनके लोकप्रिय व्यक्तित्व और महात्मा गांधी के लगाव से अभिभूत थी। इंदिरा ने कांग्रेस विभाजन कर समर्पित समर्थकों की टुकड़ी खड़ी की, जिनमें से कुछ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बने। उनमें असुरक्षा का बोध नहीं था क्योंकि वे पार्टी से बड़ी थीं। अब सोनिया ने उसे अपनी संतानों को सौंप दिया है। गांधी परिवार की भारत की खोज त्रासदियों के माध्यम से निरंतरता की रही है। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना संजय गांधी और उनकी माता के निधन का परिणाम था।

जब बोफोर्स घोटाले का विवाद उठा, तो उनके नजदीकी भाजपा में चले गये, जहां वे मंत्री एवं सांसद बने। विडंबना देखें, उनमें अधिकतर कांग्रेस नेताओं के परिजन थे। अब राहुल को कांग्रेस को एकजुट रखना होगा तथा उसे युद्ध के लिए तैयार करना होगा। भाजपा के दूसरे स्तर के नेता अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं, जबकि कई कांग्रेस नेता युवा या अधेड़ हैं और कुछ साठ के दशक के शुरू में हैं। सचिन पायलट, रेवंत रेड्डी, डीके शिवकुमार, गौरव गोगोई, नाना पटोले, दीपेंदर हुड्डा, शशि थरूर, भूपेश बघेल आदि अकेले और साथ मिलकर अपने क्षेत्रों में जीत दिला सकते हैं। जनवरी, 2013 में जयपुर में राहुल ने मीडिया को कहा था- 'कांग्रेस एक मजेदार पार्टी है।

यह दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, पर शायद इसमें एक भी नियम या कायदा नहीं है। हम हर दो मिनट में नये कानून बनाते हैं, फिर उन्हें हटा देते हैं। पार्टी में नियमों के बारे में किसी को पता नहीं।' राहुल को केवल एक नियम का पालन करना चाहिए- खो गये गांधी जादू को पुन: सक्रिय करना। वे अगला प्रधानमंत्री बनने से बस एक कदम दूर हैं। पप्पू से प्रतिपक्ष का नेता बनने का उनका रूपांतरण उनकी दो यात्राओं के कारण विश्वसनीय है। उन्हें याद रखना चाहिए कि गांधी परिवार के, गांधी परिवार द्वारा और गांधी परिवार के लिए कांग्रेस अब आगे नहीं चल सकती। अब तक वह बची रही है, पर यदि उसे आगे बढ़ना है, तो उसे लोगों की कांग्रेस बनना होगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *साध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

नींद लेने के नाम से दिल में दस्तक देता है खौफ, जानें सोम्नीफोबिया की बीमारी कितनी खतरनाक?

सोम्नीफोबिया की बीमारी क्या है? दरअसल इसे आम बोलचाल और हेल्थ एक्सपर्ट के भाषा में कहेंगे सोने के नाम पर अजीब सा डर लगना। आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको अर्ली मॉर्निंग जरूरी काम के लिए फ्लाइट पकड़नी है। आप इस चक्कर में पूरी रात नहीं सोते हैं कि अगर आप सो गए तो फिर आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। अनहोनी हो जाएगी। कई तरह से सवाल दिमाग में आते हैं। इतनी सारी बातों के बीच दिमाग इतना ज्यादा उलझ जाता है कि आपको लगता है कि कुछ अनहोनी हो जाए इससे अच्छा है कि पूरी रात जगने में ही भलाई है।

सोमनीफोबिया के लक्षण

यह तो एक मामूली सी बात हो गई लेकिन ऐसा ही डर कुछ लोगों के अंगर गंभीर रूप ले लेता है और यह सोमनीफोबिया की बीमारी का शिकार बना देता है। इस बीमारी के मरीज सोते ही नहीं है। उन्हें सोने के नाम से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर सो गए तो कुछ अनहोनी घट जाएगी। अगर बिस्तर पर लेटेंगे भी तो उनके शरीर पर अजीबोगरीब चीजें दिखाई देगी। जिसे सोमनीफोबिया के लक्षण कहे गए हैं। जैसे माथे से पसीना, नम हथेलियां, तेज़ दिल धड़कना।

सोम्नीफोबिया के लक्षण नींद की कमी के कारण पूरे दिन काफी ज्यादा थकावट रहता है। हालांकि, ऐसे शारीरिक लक्षणों के अलावा, मनोवैज्ञानिक लक्षण भी हैं। हाइपरवेंटिलेशन, सीने में दर्द, कोल्ड फ्लश, कंपन और कंपन, मतली, उल्टी, दिल की धड़कन तेज होना

के मुताबिक पार्किंसंस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिमेंशिया, डिप्रेशन जैसी बीमारी में लोगों में फोबिया को अधिक गंभीर बीमारी का लक्षण माना जाता है।

मनोवैज्ञानिक लक्षण जो किसी व्यक्ति में हो सकते हैं वे हैं-

विनाश की आशंका, अलगाव की भावना, चिंता और घबराहट के दौरे, नींद में देरी, सोने के समय से बचना

सोम्नीफोबिया से बचने के लिए करें यह उपाय

रोजाना एक्सरसाइज करें, अच्छा डाइट लें और सोने से पहले किताब जरूर पढ़ें। कम से कम कैफीन का इस्तेमाल करें। दिन के वक्त झपकी लेने से बचें।

पहली बार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं मराठी एक्ट्रेस हृता दुर्गुले

मराठी एक्ट्रेस हृता दुर्गुले थ्रिलर सीरीज कमांडर करण सक्सेना में पहली बार एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने जा रही हैं। उन्होंने अपने किरदार के बारे में खुलकर बात की।

रचना म्हात्रे की भूमिका निभाने को लेकर हृता ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, रचना का किरदार निभाना एक शानदार अनुभव रहा है। किरदार में कई रंग हैं, इसलिए मैं दृश्यों को करते हुए बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाई। मेरे निर्देशक जतिन वागले सर ने शूटिंग के दौरान मेरा बहुत साथ दिया। उन्हीं की वजह से मैं पुलिस और रॉ की बारीकियों को समझ पाई।

हृता ने कहा, मैं पहली बार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हूं। सच कहूं तो, मैं स्पेशल ऑपरेशन जैसे शो की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं। मैं एक कलाकार के तौर पर उस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी। मैं इसके लिए आभारी हूं कि मैं रचना का किरदार निभा पाई। रचना का कभी हार न मानने वाला रवैया मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है। एक अच्छी बेटी और एक अच्छी पुलिस अधिकारी बनने की उसकी निरंतर लड़ाई मुझे उसकी मानवता से प्यार करने पर मजबूर करती है।

जतिन वागले द्वारा निर्देशित और कीलाइट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित कमांडर करण सक्सेना को अमित खान ने लिखा है।

इस सीरीज में गुरमीत चौधरी मुख्य भूमिका में हैं और इकबाल खान भी हैं। यह एक निडर रॉ एजेंट की कहानी है जो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़े राजनीतिक रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है।

यह सीरीज 8 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर हुई।

हृता ने अनन्या, टाइमपास 3, सर्किट और कन्नी जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है।

शब्द सामर्थ्य -139

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. अभिमान, घमंड, अनुमान 4. बादल, मेघ, जलद (सं) 6. अधिकार वाला, अधिकारी 8. गति, सामंजस्य, समा जाना 10. कारावास, जेल 11. जोर, शक्ति, जान, सांस 12. राजाओं के रहने का भवन 15. मालामाल, अमीर, धनवान 18. नाव खेने का यंत्र 20. 'खन' ध्वनि उत्पन्न होना, पायल आदि का शब्द करना 21. मार डाला हुआ, घायल किया हुआ 22. हमेशा, आवाज 23. आग की लपट, ज्वाला 24. झगड़ा, तकरार 25. हीरा।

ऊपर से नीचे

1. दोषी, अपराधी 3. ताश में नौ अंक वाला पत्ता 4. झंडा, पताका 5. गहरा कीचड़, पंक 7. बूंद, अंश 9. मृत्यु के देवता 13. संसार, दुनिया, जग 14. हुजूर, जनाब, सम्मान सूचक एक शब्द (उ.) 16. सच्चा, धर्मनिष्ठ, ईमानवाला 17. अनूठा, बांका, अनुपम, छैला 18. आश्रय, शरण 19. साधुवाद, प्रशंसा 20. पटवारी की ऐसी बही जिसमें खेत संबंधी अनेक बातें लिखी जाती है, एक प्रकार का दानेदार संक्रामक रोग 23. गम, मातम, दुख।

1		3	■	■	4		5	■
	■	6	7			■	8	9
10				■		■	11	
	■	■	12	13		14		■
15	16		■		■		■	17
■		■	18		19		■	
20				■	21		■	
22		■		■		■	23	
24		■	■	■	25			■

शब्द सामर्थ्य क्रमांक138 का हल

स्मृ	ति	■	पा	व	क	■	बे	ल
■	र	ज	नी	च	र	■	■	ट्टू
मु	स्का	न	■	न	म	की	न	■
सा	र	■	स	■	■	ट	ख	ना
फि	■	अ	जा	य	ब	■	रा	जा
र	च	ना	■	था	ल	■	■	य
■	■	धि	■	र्थ	■	स	मा	ज
उ	प	कृ	त	■	आ	वा	ज	■
ल्लू	■	त	■	■	ब	ल	रा	म

बढ़ता रक्षा उत्पादन

संजना मेहता

वर्ष 2023-24 में भारत का कुल वार्षिक रक्षा उत्पादन 1. 3 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो एक रिकॉर्ड है। वित्त वर्ष 2022-24 की तुलना में बीते वर्ष 16. 7 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सही कहा है कि 'मेक इन इंडिया' अभियान साल-दर-साल नये नये मील के पत्थर पार कर रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एवं प्रयासों के सकारात्मक परिणाम तो अनेक क्षेत्रों में दिख रहे हैं, पर रक्षा उत्पादन एवं निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि का एक विशिष्ट महत्व है।

ऐतिहासिक रूप से हम अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर रहे हैं। कुछ वर्षों से भारत सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि हमारी सेनाएं कई वस्तुओं की खरीद देश में ही करेंगी। इन वस्तुओं की सूची लगातार बड़ी होती जा रही है। युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण भी भारत में हो रहा है। इनके निर्माण की क्षमता कुछ गिने-चुने देशों के पास ही है। आयात घटने और निर्यात बढ़ने से खर्च में कमी आ रही है और रक्षा उद्योग की कमाई में बढ़ोतरी हो रही है। हथियारों की आपूर्ति में भू-राजनीतिक स्थितियों तथा तकनीक को लेकर विभिन्न देशों की संरक्षणात्मक नीतियों का भी प्रभाव होता है।

देश में उत्पादन बढ़ने से ऐसे दबावों में भी कमी आ रही है। जिन देशों को रक्षा उत्पाद बेचे जा रहे हैं, उनके साथ हमारे रणनीतिक संबंध भी बेहतर हो रहे हैं। इससे वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिल रही है। निर्यात में वृद्धि यह भी इंगित करती है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि आयातकों में अमेरिका, ब्रिटेन, इस्राइल, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सऊदी अरब आदि देश शामिल हैं। इनमें से अनेक देश विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं तथा रक्षा उत्पादन में शीर्षस्थ हैं।

बीते वित्त वर्ष में कुल उत्पादन (मूल्य के हिसाब से) का 79 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित किया गया और शेष योगदान निजी क्षेत्र ने किया। इससे स्पष्ट है कि सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने समेत विभिन्न सुधारों के परिणाम उत्साहजनक हैं। वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रहा, जो अभूतपूर्व है। साल 2022-23 में यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रहा था। रक्षा उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि की गति के बने रहने की पूरी संभावना है, जिसका एक संकेत हमें शेयर बाजार में संबंधित कंपनियों के प्रदर्शन से मिलता है। इसे ठोस आधार देने के लिए शोध एवं अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम अत्याधुनिक तकनीक आधारित साजो-सामान का उत्पादन बढ़ा सकें।

टीएमसी सांसद को तगड़ा झटका

दिल्ली हाई कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को मानहानि के मामले में कोर्ट ने उन्हें पचास लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।

लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक सचिव हैं। अदालत ने माफीनामा प्रमुख अंग्रेजी अखबार में छपवाने और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने को भी कहा है, जो छह माह तक नजर आना चाहिए। लक्ष्मी की याचिका के अनुसार गोखले ने 2021 में 13 और 23 जून को पुरी दंपति पर 2006 में स्विट्जरलैंड में काले धन से घर खरीदने की बात कही थी। गोखले द्वारा पोस्ट किया गया था कि स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन की जांच करे। अदालत ने वादी के खिलाफ आगे भी कोई अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका है। साथ ही, उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई कोई भी राशि नहीं कर सकने की बात भी कही है। फिलवक्त लक्ष्मी पुरी किसी औपचारिक भूमिका में नहीं हैं परंतु उनकी निजी उपलब्धियों और राष्ट्र सेवा पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता।

हालांकि अदालती कार्यवाही के दौरान साकेत गोखले अपने रुख पर कायम रहे। कहना गलत नहीं होगा कि साक्ष्य मौजूद होने पर ही उन्हें सार्वजनिक प्लेटफार्म पर इस तरह के आरोप लगाने थे। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले गोखले राहुल गांधी से प्रभावित रहे हैं पर कांग्रेस से 2019 में उन्होंने संबंध तोड़ लिया था। क्राउड फंडिंग द्वारा जुटाए गए पैसों की हेराफेरी के आरोपों में 2022 में गोखले को गुजरात पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरापों में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे में भी वह आ चुके हैं। दागदार छवि के बावजूद साकेत गोखले दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछाल कर अपने पद की गरिमा को भी चुटहिल कर रहे हैं। रही बात राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की तो उसका भी तो कोई स्तर होना चाहिए। राम मंदिर के खिलाफ और प्रधानमंत्री की अघोषित संपत्ति जैसे मामलों पर याचिकाएं लगा कर सिर्फ विवाद उत्पन्न करना राजनेता को शोभा नहीं देता। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भी अपने इस प्रवक्ता पर सख्ती करनी चाहिए। इससे उनके दल की छवि भी कम धूमिल नहीं होती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, उच्च सदन का सदस्य होने के बावजूद मानहानि का हक नहीं मिल सकता। (आरएनएस)

अभिनेत्री मालविका की तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस मालविका मोहनन हमेशा अपने बोल्ड लुक्स के कारण चर्चाओं में रहती हैं। एक्ट्रेस जब भी अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं तो वो चंद ही मिनटों में वायरल होने लगती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में उनका स्टनिंग अंदाज देखकर फैंस उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं।

एक्ट्रेस मालविका मोहनन हमेशा अपने बोल्ड लुक्स के कारण सोशल मीडिया पर छाई हुई रहती हैं। उनका फैशन स्टेटमेंट अक्सर फैंस के बीच ट्रेंड करता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में उनका स्टनिंग लुक देखकर फैंस अपने होश खो बैठे हैं।

मालविका मोहनन ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान बेहद ही खूबसूरत व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वो काफी गॉर्जियस नजर आ रही हैं।

इन फोटोज में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस मालविका मोहनन कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक कातिलाना अंदाज में पोज देते हुए सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा रही हैं। बता दें कि एक्ट्रेस जब भी अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं तो उनका हर एक लुक लोगों के बीच वायरल होने लगता है। चाहें इंडियन हो या वेस्टर्न एक्ट्रेस अपने हर अंदाज में कहर ढाती हैं।

खुले बाल, न्यूड मेकअप लुक कर के एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने अपने आउटलुक को बेहद खूबसूरती के साथ निखारा है।

मालविका मोहनन के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस रजनीकांत की फिल्म पेट्टा, मास्टर, पट्टम रोल, मारन जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

शमा सिकंदर ने स्विमिंग पूल में लगाई आग

टीवी एक्ट्रेस शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर हमेशा ही अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों से धमाल मचाती रहती हैं. आए दिन वह अपनी हॉट तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस को दीवाना बनाती रहती हैं. हाल ही में, शमा ने फिर से इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह स्विमिंग पूल में एनिमल प्रिंटेड मोनोकिनी पहने नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों में शमा लाइट मेकअप और खुले बालों के साथ बेहद हॉट लग रही हैं. उन्होंने पोज देते हुए अपनी टोन्ड बॉडी को फ्लॉन्ट किया है. शमा की इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

टीवी एक्ट्रेस से लेकर बॉलीवुड का सफर तय करने वाली शमा सिकंदर आए दिन अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर खबरों में रहती हैं।

उनका कातिलाना अंदाज इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही इंटरनेट का पारा हाई कर देता है।

एक्ट्रेस शमा सिकंदर आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस अदाओं के चलते लाइमलाइट में रहती हैं। उनका हर एक अंदाज इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही कहर बरपाता है।

बता दें एक्ट्रेस शमा सिकंदर जब भी अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं तो फैंस उनकी हर एक फोटोज पर लाइक्स और कॉमेंट्स के जरिए अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं।

प्रशासनिक विफलता का नतीजा है हाथरस हादसा

आचार्य प्रमोद कृष्णम

हाथरस की घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों की इस दुखद घटना में जान गयी है, उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि और जो घायल हुए हैं, वे जल्दी स्वस्थ हों, इसकी कामना करता हूं। इस घटना को लेकर तरह-तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा नहीं है। यह राजनीतिक संवेदनशीलता, व्यवस्था और दूरदर्शिता का मुद्दा है। यह स्थानीय पुलिस-प्रशासन की लापरवाही का विषय है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पर मिलकर सोचने की जरूरत है क्योंकि व्यवस्था के अभाव में इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है।

इसलिए मेरा आग्रह है कि घटना के कारणों का पता लगाया जाए और भविष्य में ऐसा न हो, इस पर विचार हो। उदाहरण के लिए, इस तरह की भीड़ जहां भी इकट्ठी होती है, वहां पुलिस-प्रशासन का रवैया बहुत लचीला होता है। चाहे सरकार किसी की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस प्रशासन के रवैये में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। इसका वे खुद साक्षी रहे हैं। हर साल कल्कि धाम में कल्कि महोत्सव मनाया जाता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कई बार मंच से उतरना मुश्किल हो जाता है। एक साथ सैकड़ों के समूह में अलग-अलग जत्थे मंच की तरफ बढ़ जाते हैं। कई बार तो सुरक्षा को लेकर खतरा लगने लगता है। उस भीड़ में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप सैकड़ों की भीड़ में असहाय हो जाते हैं। पुलिस-प्रशासन तभी तक चुस्त-दुरुस्त दिखता है, जब कोई वीआइपी आते हैं। उनके जाने के साथ ही पुलिस रिलैक्स हो जाती है। मैंने इस विषय में कई बार पुलिस अधिकारियों को भी बताया है कि ऐसे आयोजन में उनकी ओर से किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं है। पुलिस-प्रशासन की अपनी कार्यप्रणाली है, जिसे वह ठीक नहीं करना चाहती है। हाथरस की घटना के लिए आयोजक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। वह भी दोषी हैं। यदि उन्होंने इन खतरों को आंकते हुए पुलिस प्रशासन से बातचीत की होती, तो शायद यह घटना नहीं घटती। पुलिस प्रशासन को इतनी संख्या में भीड़ के आने का अंदेशा होता, तो अपनी ओर से शायद वह भी कुछ कर पाता।

क्योंकि ऐसी घटना जहां होती है, उसकी तैयारी अगर पहले से न हो, तो व्यवस्था और अधिक चरमरा जाती है क्योंकि वहां एंबुलेंस, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, दवाओं आदि की व्यवस्था नहीं होती। जहां तक भक्तों की श्रद्धा की बात है, तो जो श्रद्धालु होते हैं, उनकी जहां श्रद्धा होती है, वे वहां जाते ही हैं। उनसे मिलना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनका पैर छूना चाहते हैं, तो ऐसे में भगदड़ मचना स्वाभाविक है। यदि मिलने के लिए या आशीर्वाद लेने के लिए एक साथ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाएं, तो भगदड़ की स्थिति होना स्वाभाविक है। इसलिए मेरी समझ से इस घटना में सबसे बड़ा दोषी स्थानीय पुलिस-प्रशासन है।

घटना के पीछे आस्था, श्रद्धा, अंधविश्वास जैसी बहुत सारी बातें बतायी जा रही हैं, लेकिन ये सब इसका दूसरा पहलू है। इन बातों पर अलग से बात की जा सकती है। अभी सबसे ,पहले हमें यह तय करना है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसी की भावना और श्रद्धा पर नहीं डाली जा सकती है। मेले लगने बंद नहीं हो सकते हैं। श्रद्धा के नाम पर लगे, तो गलत और कहीं और किसी राजनीतिक रैली के नाम पर लगे तो सही- इस तरह के दोहरे मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि जो भीड़ है, वह कितनी है और किस प्रकार की है।

जो राजनीतिक रैली होती है, उसमें भीड़ क्या नेताओं से नहीं मिलना चाहती है? उसके साथ सेल्फी नहीं लेना चाहती है, कई बार भीड़ के कारण मंच तक टूट जाते हैं। इसलिए इस तरह के मेलों को अंधविश्वास आदि से जोड़कर देखना मेरी समझ से उचित नहीं है। मेरा बार-बार यही कहना है कि कोई भी राजनीतिक रैली हो, मेला या आयोजन हो, उसमें भीड़ जुटती ही है, जरूरत इस बात की है कि उस भीड़ को नियंत्रित कैसे किया जाए, और यह काम स्थानीय पुलिस ही बेहतर तरीके से कर सकती है।

जहां तक अंधविश्वास की बात है, तो मेरा मानना है कि भारत भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, श्रद्धा और विश्वास का देश है। हम अपनी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के बजाय हम अपनी परंपराओं, आस्था और विश्वास को कटघरे में खड़ा करें, तो मुझे लगता है कि यह नाइंसाफी है।

एक बात और बताना चाहता हूं कि अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है। जहां विश्वास होता है, वह अंधा ही होता है। आप विश्वास किसे कहेंगे? विश्वास भी तो अंधा ही होता है। आप किसी को घर पर खाना के लिए बुलायेंगे, तो वह व्यक्ति आपके घर के सब्जी को 'टेस्ट' करके तो नहीं खायेगा कि कहीं उसमें किसी तरह का जहर तो नहीं मिला है। यदि कोई मिला भी दे, तो उसमें उस व्यक्ति का क्या कसूर है? तो, जो श्रद्धालु है, उस पर आरोप न लगाया जाए। और, इस पर राजनीति न की जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इतनी दुखद घटना पर लोग राजनीति कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों से भी कहना चाहता हूं कि वे लाशों पर राजनीति न करें। यह समय राजनीति का नहीं है। मृतकों के परिवार के लिए यह बहुत ही दुखदायी क्षण है।

उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरी अपेक्षा है कि वह इसकी निष्पक्ष जांच करेगी और जिन लोगों की लापरवाही रही है, उसे दंडित करेगी। सरकार पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद को यह निर्देश दें कि जहां भी रैली, सभा या मेला आयोजित हो रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस-प्रशासन के ऊपर हो। इसी तरह के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही देश में कहीं भी न हो। निश्चित रूप से यह प्रशासनिक विफलता, लापरवाही और अपरिपक्वता का परिणाम है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना कोई न कोई ऐसी घटना घटती रहेगी और निर्दोष लोगों की जान चली जायेगी। जहां भी लोग बड़ी संख्या में जमा होते हैं, वहां किस प्रकार से प्रभावी इंतजाम हों, इस संबंध में एक व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किया जाना चाहिए। इस तरह के आयोजन की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होनी चाहिए, न कि श्रद्धालुओं के आस्था पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा करना चाहिए।

बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त

राजधानी दिल्ली में बारिश ने 88 वर्षो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जन-जीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

अगले कुछ दिन तेज वर्षा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भारी बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में भी काफी गिरावट आई है। मगर कई इलाकों में जल-भराव के चलते दिल्ली के सारे विकास की हालत पस्त हो गई है।

मानसून आगमन के कारण हुई तीन घंटों तक मूसलाधार बरसात के कारण दिल्ली हवाई अड्डे में छत का एक हिस्सा गिरने से एक वाहन चालक की मौत हो गई। साथ ही, अन्य संबंधित घटनाओं में भी सात अन्य लोगों की अलग-अलग मौत हो गई। पुलिस अभी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है।

भीषण गर्मी के मार झेल रहे दिल्ली वाले मानसून के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर सामान्य से दो दिन पूर्व हुई इस जबरदस्त बरसात ने रहवासियों को बुरी तरह भयभीत कर दिया है। मोहल्ले और बस्तियां ही पानी में नहीं डूबी हैं, बल्कि कई अति व्यस्त अंडरपास भी बरसात के पानी से लबालब भर गए।

समूची दिल्ली ट्रैफिक जाम के चलते थम सी गई। यह कोई पहली बार नहीं है, जब दिल्लीवासियों को जल भराव जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। हर साल राज्य सरकार का तंत्र घोर लापरवाही करता रहता है और अंत में केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़कर अपने ढें पर चल पड़ता है।

दिल्ली ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रति वर्ष देश भर में जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों मौते होती हैं, और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। सिर्फ चमचमाती सडक़ों, फ्लाईओवरों और दमकती रोशनी को विकास का पर्याय नहीं माना जा सकता।

बल्कि पानी की उचित निकासी और बरसाती पानी के भंडारण की सटीक व्यवस्था की जरूरत ज्यादा है। दरअसल, यह दिल्ली की ही समस्या नहीं है, बल्कि देश के तमाम बड़े शहरों और महानगरों में बारिश होते ही सवाल उठते लगते हैं कि हमारे विकास में क्या खामियां हैं, जो एक ही बारिश में शहर पानी-पानी हो जाते हैं।

बरसात में लोगों की परेशानी पर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि मौसम की मार से जनता को बचाने की पूर्व तैयारियों पर जोर दे। राज्य सरकारों को भी सख्ती से मुस्तैद रहने की नसीहतें दी जाएं। (आरएनएस)

सू- दोकू क्र. 139

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.138 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

खुद की तरफ मुड़ी उंगलियां भी देखनी होंगी

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नफरत फैलाने वाले भाषणों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों और प्रार्थना स्थलों को ध्वस्त करने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये बातें कहीं। उन्होंने दुनिया भर में लोगों की धार्मिक आजादी की रक्षा के लिए काफी जद्दोजहद करने की भी बात उठाई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 28 में से 1० राज्यों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून हैं, जिनमें से कुछ राज्य विवाह के उद्देश्य से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दंड भी लगाते हैं। इसमें दुनिया के तकरीबन दो सौ देशों की धार्मिक स्थिति का आकलन किया गया है।

हालांकि भारत इसे पहले से ही खारिज करता रहा है और इसे प्रकाशित करने वाले आयोग को पक्षपाती बताता है। सिखों, ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा से निपटने में मोदी सरकार की नाकामी की बात कर रही है यह रिपोर्ट।

इसमें 2०23 में गैर- सरकारी संगठनों ने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 687 घटनाओं का जिक्र भी किया गया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 37० हटाने, मणिपुर हिंसा, ईसाइयों पर हमले, चर्च में तोड़-फोड़ और धर्मांतरण कानून के तहत हिरासत में रखे लोगों की चर्चा भी है।

चीन, ईरान, रूस, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बर्मा के साथ भारत का नाम रखे जाने पर सरकार द्वारा जताई गई आपत्ति उचित है। कहना गलत नहीं है कि मोदी सरकार अपनी हिन्दुत्ववादी विचारधारा के चलते बहुसंख्यकों को प्रभावित करने में सफल है।

इसलिए हर साल अमेरिका को इस पर पुनः विचार करने की बात करने की बात कर रस्मादायगी कर लेती है, जबकि सरकार को अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी छवि सुधारने के प्रयास करने चाहिए। संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक आजादी मौलिक अधिकार है।

इसलिए सभी धर्मावलंबियों की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है। वहीं अमेरिका में अेतों को लेकर जो पक्षपात होते हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। दूसरों पर उंगली उठाते हुए, खुद की तरफ मुड़ी उंगलियां भी देखनी होंगी।(आरएनएस)

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया वृक्षारोपण

संवाददाता

देहरादून। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया।

आज यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा उत्तराखंड के लोक प्रिय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने की चलाई गई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एकता विहार में 500 पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने युवाओं का मार्गदर्शन किया।

शिव सिंह बिष्ट ने युवाओं को एक साल तक एक पेड़ की जिम्मेदारी लेने का संकल्प दिलाया। वृक्षारोपण मे महानगर उपाध्यक्ष पारस गोयल, महानगर मंत्री कार्तिक जेटली, टॉय संस्था के सचिव यश बिष्ट कार्यालय प्रभारी आदर्श वर्मा, महानगर कार्यकारणी सदस्य वैशाली बंसल, सुधांशु तिवारी, नवीन, दीपक, विशाल खेड़ा, आदि कई कार्यकर्ता एवंम पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वित्तीय अनियमितताओं पर पूर्व ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज

संवाददाता

देहरादून। वित्तीय अनियमितताओ पर पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप दयाल ने चकराता थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि ग्राम छुल्टाड की पूर्व प्रधान मुन्नी देवी द्वारा ग्राम छुल्टाड में वर्ष 2014 से 2019-2020 में किये गये दस्तावेज एवं सरकारी सम्पत्ति के घोटालों में प्रस्तुत प्रस्तुत्तर में गम्भीर वित्तीय अनियमितता होना परिलक्षित हुआ है। पुलिस ने पूर्व प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विवाहिता की मौत पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संवाददाता

देहरादून। विवाहिता की मौत पर पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम आर्स पटटी धमानस्यू टिहरी निवासी सुरेन्द्र सिंह ने डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पुत्री आरती का विवाह दीपक खत्री के साथ हुआ था। विवाह के बाद से दीपक उसकी पुत्री को परेशान करता था तथा आये दिन शराब पीकर घर में आता और मारपीट करता था। जिससे परेशान होकर उसकी बेटी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

गेस्ट हाउस में चल रहा था देह व्यापार...

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

गिरफ्तार आरोपियों के नाम (गैंग लीडर व गेस्ट हाउस संचालक) मुस्तफा पुत्र रसीद निवासी ग्राम महमूदपुर थाना पिरान कलियर जनपद हरिद्वार, आदिल पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी पहाड़गंज नबी करीम सेंट्रल दिल्ली हाल निवासी मैनेजर होटल रहमत साबरी पिरान कलियर, मोहम्मद दानिश अलीम पुत्र सरफराज निवासी बहेरा थाना भोपा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, शौकत पुत्र लतिम निवासी भीम सिंह वाली गली खलासी लाइन सदर बाजार सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सलीम पुत्र मुजफ्फर निवासी जयंतीपुर मझोला मुरादाबाद, वसीम पुत्र मुंशी निवासी भुजा हेडी पुरकाजी मुजफ्फरनगर, असलम पुत्र नजीर निवासी बीबीपुर छज्जल मुरादाबाद, अलीजान पुत्र जाबिर निवासी अकबरपुर झोझा थाना झबरेड़ा हरिद्वार, पुष्पेंद्र पुत्र नरेंद्र निवासी किशनपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार व अजय उर्फ काला पुत्र धर्मवीर निवासी किशनपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार बताये जा रहे है। जिनके साथ आठ महिलाए भी गिरफ्तार की गयी है। संयुक्त टीम ने मौके से काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री व धनराशि भी बरामद की है।

डॉक्टर ने कराया, छात्रसंघ अध्यक्ष सहित पांच छात्रों पर मुकदमा

विरोध में छात्रों का कोतवाली में जमकर हंगामा

हमारे संवाददाता

नैनीताल। चिकित्सक पुनीत कुमार गोयल से मारपीट के मामले में छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई पर बीते रोज छात्रों ने कॉलेज से कोतवाली तक जमकर हंगामा काटा। छात्र नेताओं ने कॉलेज में तालाबंदी और हंगामा करते हुए प्रवेश का पहला दिन बाधित कर दिया। जिसके बाद छात्र नेताओं का गुट कोतवाली पहुंच गया। पहले कोतवाली घेरकर हंगामा किया और फिर सीओ दफ्तर में घुसकर सीओ के सामने नारेबाजी की गयी।

बता दें कि मुखानी में केवीएम स्कूल के सामने रेडिएंट हॉस्पिटल में बीती 5 जुलाई को छात्रों द्वारा डॉ.पुनीत कुमार गोयल के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में मुखानी पुलिस ने चिकित्सक की तहरीर पर छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला, विशाल सैनी, हितेश जोशी, राहुल मठपाल, मनीकेत तोमर, मोहित खोलिया व अन्य अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तब से छात्र संघ अध्यक्ष सहित सभी आरोपी फरार हैं।

वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए छात्र नेता बड़ी संख्या में मूर्ति राम बाबू राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंच गए। जहां छात्र नेताओं ने हंगामा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया बाधित कर दी और कॉलेज गेट में ताला डाल दिया। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन छात्र नेताओं ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं होने दी। जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कोतवाली पहुंच गए। करीब आधा घंटा नारेबाजी और हंगामा करने के बाद सभी सीओ सिटी के दफ्तर में घुस गए। यहां छात्रों ने सीओ सिटी नितिन लोहनी का घेराव कर लिया और नारेबाजी करते हुए पुलिस पर गलत मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। सीओ नितिन लोहनी ने छात्रों का भरोसा दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। छात्र नेताओं का कहना है कि बुधवार को छात्रसंघ की ओर से एमबीपीजी का छात्र अभिषेक सैनी कोतवाली में डॉक्टर गोयल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गया था। कोतवाली में पुलिस ने उसे कई घंटो बैठाए रखा और फिर भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। इसे लेकर छात्रों ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है।

छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्पताल में उनका साथी भर्ती था, जिसके डिस्चार्ज होने पर उन्होंने डॉक्टर से बिल कम करने के लिए कहा था और इसी बात पर डॉक्टर गोयल ने उनसे बदसलूकी शुरू कर दी और फिर हाथापाई शुरू हो गई। छात्रों ने डॉक्टर की दराज से रुपये निकालने के आरोप भी गलत बताया है। छात्रों ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज चेक कराने की मांग की है।

1.235 किलो चरस सहित तस्कर दबोचा

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से 1.235 किलो चरस, तस्करी में प्रयुक्त आई-20 कार व इलेक्ट्रानिक तराजू भी बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार बीते रोज कोतवाली ज्वालापुर पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कोई नशा तस्कर नशीले पदार्थो की डिलीवरी हेतू आने वाला है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में चैकिंग अभियान चला दिया। इस दौरान पुलिस को दशहरा मैदान

तस्करी में प्रयुक्त कार व इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद

नहर पटरी के पास एक संदिग्ध आई-20 कार आती हुई दिखायी दी। पुलिस ने जब उसे रोकना चाहा तो कार चालक कार छोड़कर भागने लगा। इस पर उसे घेर कर दबोचा गया। कार की तलाशी के दौरान उसमें रखा 1.235 किलो चरस व इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मोहल्ला कचहरी सराय जलालाबाद नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश बताया।

पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

आयोग की विभिन्न पदों पर करायी जा रही परीक्षा में हुई है धांधली: भण्डारी

संवाददाता

देहरादून। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भण्डारी ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा कराई जा रही राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की विभिन्न पदों पर हुई परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है।

आज यहां युवा कॉग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भण्डारी द्वारा कांग्रेस भवन देहरादून में प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा करवाई जा रही राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के विभिन्न पदों पर आयोजित की जा रही परीक्षा में गंभीर धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य के कुल 13 रिक्त पदों पर 6 और 7 अप्रैल को परीक्षा करवाई गई थी। 25 जून से 28 जून, 2024 तक लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार

परीक्षा संपादित की गई थी। इसके बाद जो अंतिम सूची उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गयी है उसमें स्पष्ट अपारदर्शिता है और गंभीर धांधली होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सामान्य वर्ग में 4 सदस्यों के लिए के रिक्त पद के सापेक्ष 8 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है जबकि अन्य पदों पर जारी की गई सूची पदों की कुल संख्या के बराबर ही है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक पदों पर अपना आवेदन किया था उनका एक ही साक्षात्कार लिया गया था लेकिन परिणाम में उन्हें अलग-अलग पदों पर अलग-अलग नंबर दिए गए। मोहन भंडारी ने कहा कि इस सम्पूर्ण को परीक्षा प्रक्रिया में स्पष्ट अपारदर्शिता दिखाई देती है जिससे कि कुछ खास अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाये और उच्च स्तरीय जांच की जाए। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश महासचिव गौरव सागर, उदित थपलियाल, मनोज राम, नमन शर्मा, हरीश जोशी, हरजीत सिंह, वैशाली पाल मौजूद रहे।

एक नजर

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को हिरासत में लिया

नई दिल्ली। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया। मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता को पूछताछ के लिए उनके आवास से ईडी दफ्तर लाया गया। बी नागेंद्र के पास अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय का जिम्मा था। आरोप लगने के बाद उन्होंने 6 जून को इस्तीफा दे दिया था। नागेंद्र ने ईडी कार्यालय ले जाते समय संवाददाताओं से कहा, मुझे मेरे घर से लाया जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। बता दें कि इस मामले में ईडी ने पिछले दो दिनों में कई स्थानों पर छापेमारी की है। इसमें पूर्व मंत्री नागेंद्र और सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दल के परिसर भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले के तहत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में लगभग 20 स्थानों पर जांच की है। इस निगम से जुड़ा अवैध धन हस्तांतरण का मामला तब सामने आया था जब इसके लेखा अधीक्षक चन्द्रशेखरन पी ने 26 मई को आत्महत्या कर ली थी। चन्द्रशेखरन ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपये के अनधिकृत हस्तांतरण का दावा किया था। उसमें से 88.62 करोड़ रुपये अवैध रूप से बड़ी आईटी कंपनियों और हैदराबाद स्थित सहकारी बैंक सहित अन्य के विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने का दावा था।

'कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है?'

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार से पूछा कि वह एक राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने अंबाला के पास शंभू बार्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने का निर्देश दिया है। किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी। सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि राज्य, उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है जिसमें उसे सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया गया था। वकील द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के बारे में पीठ को सूचित किए जाने पर न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि इसे खोलिए, लेकिन नियंत्रित कीजिए।

बस और लॉरी की भीषण टक्कर में 9 यात्रियों की मौत

नई दिल्ली। कर्नाटक के कोलार में एक भीषण सड़क हादसा होने से 9 लोगों की जान चली गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया। वहीं, मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया गया है जिनकी पहचान के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल हादसे के असल कारण का पता नहीं चल सका है कि इस हादसे में लॉरी ड्राइवर की गलती थी या बस चालक की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर ही है और घायलों को निश्चित इलाज मुहैया करा रही है। कर्नाटक में 24 घंटों के भीतर हुआ ये दूसरा बड़ा हादसा है। गुरुवार को ही मांड्या जिले के नागमंगला तालुक में श्रीरामनहल्ली गेट के पास एक कार और कैंटर वाहन के बीच टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई थी। कार होलालकेरे से मैसूरु जा रही थी तभी यह हादसा हुआ। ऐसे सड़क हादसे आये दिन हो रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी।

दिल्ली में केदारधाम पर छिड़ा राजनीतिक संग्राम

धामों की फ्रेंचाइजी बांट रही है भाजपाः कांग्रेस

विशेष संवाददाता

देहरादून। दिल्ली में केदारनाथ धाम के लिए सीएम धामी ने भूमि पूजन करते समय भले ही धर्म और सनातन की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की शान में बहुत सारी बातें कही गई हो लेकिन अब देश में कहीं भी धामों की स्थापना को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है उस पर भाजपा और उसके नेताओं को कोई जवाब देते नहीं बन रहा है।

एक तरफ अब जहां राजनीतिक दलों के नेता सीएम धामी के इस काम को देवभूमि की संस्कृति का अपमान बता रहे हैं वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित, पुजारी और पंडा इसके विरोध में आंदोलन पर उतर आए हैं। उन्होंने सीएम को चेतावनी दी है कि वह अपना फैसला वापस ले नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने इसे गढ़वाल के साथ भेदभाव भी बताया है। एक अन्य बात यह है कि जब सीएम धामी दिल्ली में भूमि पूजन कर रहे थे तब उनके साथ हरिद्वार के महामंडलेश्वर भी मौजूद थे जो धार्मिक मामलों के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने भी सीएम को इस मामले में अपनी राय क्यों नहीं दी। अगर सीएम धामी को कुछ ऐसा करना ही था तो तीर्थ पुरोहित व बद्री केदार

●भाजपा नेताओं में धाम बनाने की लगी होड़ः हरीश

●किसी भी धाम को दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं

समिति को अपने विश्वास में लेना चाहिए था।

इस बाबत केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर का साफ कहना है कि जो भी धाम जहां है सिर्फ वहीं धाम होगा अनियंत्रित किसी भी स्थान पर कोई भी धाम नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि हिमालय के जिस केदार खंड में केदारनाथ धाम है वह केदार खंड में ही रहेगा दिल्ली में नहीं हो सकता है। दिल्ली में केदार धाम मंदिर के लिए भूमि पूजन किये जाने के विरोध में कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने तो उपवास करते हुए यहां तक कहा है कि भाजपा धामों की फ्रेंचाइजी देकर उत्तराखंड के धामों का न सिर्फ मजाक बना रही है बल्कि देवभूमि की संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रही है।

उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा के नेताओं में धाम बनाने की होड़ लगी हुई है। जिसकी जहां मर्जी आया वहीं धाम बना दे उन्होंने कहा कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं लेकिन भाजपा सैन्य धाम के नाम पर राजनीति कर रही है 3 साल हो चुके हैं सैन्य धाम के नाम पर भाजपा ने क्या किया है, प्रदेश की जनता देख रही है इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी कई तरह के सवाल किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के भूमि पूजन को भी वह गलत नहीं ठहरा पा रहे हैं और न सही ठहरा पा रहे हैं।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के जिस धर्म के मुद्दे के सहारे भाजपा ने अपनी दो संसदीय सीट से सफर शुरू कर 282 तक पहुंचाया, इसी अयोध्या के मुद्दे ने उसे भले ही अयोध्या में औंधे मुंह पटक दिया हो लेकिन भाजपा को अभी भी लगता है कि धर्म और मंदिर-मस्जिद तथा हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा ही एकमात्र उसका मुख्य राजनीतिक आधार है। वह धाम और मंदिर तथा मानस मंदिर कॉरिडोर के दम पर ही अपनी राजनीति चलाती रहेगी और उसे जन सरोकारों के मुद्दों की कोई जरूरत नहीं है।

अज्ञात वाहन की चपेट में आकर महिला घायल

संवाददाता

देहरादून। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर महिला के घायल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रांझावाला निवासी राजकुमार पाल ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पत्नी पैदल घर की तरफ आ रही थी जब वह मथुरा फार्म के पास पहुंची तो अज्ञात वाहन ने उसको अपनी चपेट में ले लिया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

दो स्कूटी चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने दो स्कूटी चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कालीदास रोड निवासी बालेन्द्र कुमार गुलाटी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह किसी काम से चन्दर नगर गया था। उसने अपनी स्कूटी आटा चक्की के बाहर खडी की थी लेकिन जब वह थोडी देर में वहा पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी स्कूटी अपने स्थान से गायब थी।

वहीं आफिसर्स कालोनी रेसकोर्स निवासी प्रतीक सिंह बोरा ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि चोरो ने दून अस्पताल के बाहर से उसकी स्कूटी चोरी कर ली है। पुलिस ने दोनों मुकदमें दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

46 लाख कीमत के मोबाइल देकर 269 फरियादियों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई

संवाददाता

नैनीताल। पुलिस ने 46 लाख रूपये की कीमत के मोबाइल लौटाकर 269 फरियादियों के चेहरे पर मुस्कान लौटायी।

आज यहां प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा फरियादियों के खोये हुये मोबाइल फोन को बरामद करने एवं त्वरित कार्यवाही करने हेतु जनपद स्तर पर गठित मोबाइल एप्प सेल को मोबाईलों को बरामद करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। प्रकाश चंद एसपी सिटी हल्द्वानी, हरबंस सिंह एसपी क्राइम/यातायात नैनीताल के निर्देशन में तथा सुमित पाण्डे क्षेत्राधिकारी ऑप्स हल्द्वानी, के पर्यवेक्षण में निरीक्षक प्रभारी, हेमचन्द्र पन्त मोबाइल एप्प (साईबर सैल) के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी किशन सिंह कुंवर, महिता कांस्टेबल पूजा चौधरी के द्वारा शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों के आधार पर माह जनवरी से जून तक नम्बरों को प्रभारी एसओजी संजीत राठौड के माध्यम से सर्विलांस में लगाये जाने के उपरान्त खोये मोबाइलों का ईएमआई का प्रचलन में होना पाया गया, उक्त मोबाईलों को विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार व पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों से कुल 269 मोबाइल फोन, मोबाईल एप्प टीम द्वारा बरामद किये गये। विभिन्न कम्पनियों के 269 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत 46 लाख 35 हजार रुपये हैं।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकारः
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालयः दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।

मो. 9358134808

नोटः सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।